



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27 पटना, बुधवार, 14 आषाढ़ 1939 (श0)  
5 जुलाई 2017 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-8	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	9-9	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	10-10	
पूरक	---	
पूरक-क	11-21	

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचनाएं  
13 जून 2017

सं० कारा/स्था० (चि०)01-03/2017-3007—दिनांक 24.04.2017 को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा राज्य की विभिन्न काराओं में Walk-in-interview के माध्यम से संविदा के आधार पर आठ (08) उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु उनके कागजातों/प्रमाण-पत्रों की जांच की गयी।

2. उपरोक्त के आलोक में सभी 08 (आठ) विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित कारा में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता (पिन कोड सहित)	आरक्षण कोटि (वास्तविक)	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ० संजय कुमार गुप्ता	स्व० गोपाल प्रसाद	मुजफ्फरपुर	ग्राम-पाराव पोखर, लेन नं०-4, पो०-रमना, थाना-काजी मोहम्मदपुर, प्रखंड-मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002	अ०पि०वर्ग	केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर
2	डॉ० जनार्दन	श्री राधेश्याम शर्मा	जहानाबाद	ग्राम/मो०-हनुमान नगर, एल०आई०जी०- 8/286, पोस्ट-थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना बिहार, 800020	सामान्य	मंडल कारा, बिहारशरीफ
3	डॉ० सत्येन्द्र कुमार	स्व० हरिराम पंजियार	भागलपुर	ग्राम+पो०-सुखराज राय पथ, घुरनपीर, बाबा चौक, छोटी खंजरपुर, जगदीशपुर, भागलपुर, 8120001	सामान्य	शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर
4	डॉ० सुनिता	श्री विवेक झा	भागलपुर	C/O डॉ० एस०एन०झा, फ्लैट नं०-102, एकान्त अपार्टमेन्ट, आर०बी० सुखराज रोड, भागलपुर, बिहार, 812001	सामान्य	महिला मंडल कारा, भागलपुर
5	डॉ० धन्वजय कुमार	श्री धुरंधर द्विवेदी	प० चम्पारण	उहमी कम्पाउन्ड, पोस्ट-रामनगर, जिला-प० चम्पारण, बिहार, 845106	सामान्य	मंडल कारा, फुलवारीशरीफ
6	डॉ० संजीव कमल	श्री उपेन्द्र पाण्डेय	वैशाली	C/O श्री उपेन्द्र पाण्डेय, अलका कॉलोनी, संदलपुर रोड, पोस्ट-महेन्द्र, बिहार, 800006	सामान्य	मंडल कारा, हाजीपुर
7	डॉ० नेहा सिंह	श्री कृष्ण कुमार सिंह	मुजफ्फरपुर	चकिया हाउस, इमलीचट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार, 842001	सामान्य	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी
8	डॉ० धीरज कुमार धीरू	श्री वृजनंदन सिंह	पटना	D.81, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना 800020	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, आरा

3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तथा असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में पंद्रह दिनों के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के अंतर्गत योगदान नहीं करने वाले चिकित्सकों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।**

13 जून 2017

सं० कारा/स्था० (चि०)01-03/2017-3008—दिनांक 24.04.2017 को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा राज्य की विभिन्न काराओं में Walk-in-interview के माध्यम से संविदा के आधार पर सैंतालीस (47) उपस्थित सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु उनके कागजातों/प्रमाण-पत्रों की जांच की गयी।

2. उपरोक्त के आलोक में सभी 47 (सैंतालीस) सामान्य चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित कारा में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता (पिन कोड सहित)	आरक्षण कोटि (वास्तविक)	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ० मुरारी शरण सिंह	श्री राधा कृष्ण सिंह	समस्तीपुर	ग्राम+पो०-महथी, थाना+प्रखण्ड-विभूतिपुर, रोसड़ा समस्तीपुर	सामान्य	उपकारा, रोसड़ा
2	डॉ० नितेश ध्वज सिंह	श्री धानू ध्वज सिंह	बेतिया	मो०-शिवपुरी, वार्ड नं०-22, बेतिया 845438	सामान्य	मंडल कारा, बेतिया
3	डॉ० मो० शरफुज्जमाँ	मो० कमरुज्जमाँ	समस्तीपुर	मखदूमी अपार्टमेन्ट, दो रूखी गली, नजदीक डेजी होटल, दरियापुर, सब्जीबाग, सम्पतचक, बाँकीपुर, पटना, पिन-800004	सामान्य	मंडल कारा, जहानाबाद
4	डॉ० मिथलेश कुमार झा	श्री जीवनाथ झा	मधुबनी	ग्राम-आवारी, थाना-सहारघाट, मधुबनी-847308	सामान्य	मंडल कारा, मधुबनी
5	डॉ० अमिताभ चौधरी	श्री सुशील प्रसाद चौधरी	प० चम्पारण	ग्राम-नोरगाबाद चौक, पो०-बेतिया, जिला-पश्चिमी चम्पारण	सामान्य	मंडल कारा, बेतिया
6	डॉ० प्रदीप कुमार	श्री दीपनारायण मंडल	भागलपुर	ग्राम-हरियो पानी टंकी, पो०+थाना-अकबर नगर, जिला-भागलपुर	अ०पि०वर्ग	शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर
7	डॉ० तारिका आई० मुस्तफा	स्व० एस०एम० मुस्तफा	पटना	ग्राम-हारुन नगर, सेक्टर-2 फुलवारीशरीफ, पटना।	सामान्य	उपकारा, पटना सिटी
8	डॉ० हरिशंकर चौबे	श्री ललन प्रसाद चौबे	बक्सर	ग्राम+पो०- पुराना भोजपुर, बक्सर-802133	सामान्य	केन्द्रीय कारा, बक्सर
9	डॉ० अब्दुल वहाव	श्री अब्दुल मन्नान	भागलपुर	ग्राम-उजानी, पो०-मनियांमोर, तहसील-नवगछिया, भागलपुर-853204	सामान्य	केन्द्रीय कारा, पुर्णियाँ
10	डॉ० मृत्युंजय कुमार	श्री विनोद प्रसाद यादव	भागलपुर	ग्राम+पो०-साहेबगंज, थाना-यूनिभरसिटी, भागलपुर	पि०वर्ग	महिला मंडल कारा, भागलपुर
11	डॉ० वरुण कुमार	श्री सुरेन्द्र कुमार	पूर्वी चम्पारण	ग्राम+पोस्ट-सिरसा, प्रखंड-मोतिहारी, जिला-पू० चम्पारण, बिहार,पिन-845401	सामान्य	मंडल कारा, कटिहार

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता (पिन कोड सहित)	आरक्षण कोटि (वास्तविक)	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
12	डॉ० रविन्द्र कुमार चौधरी	श्री राघो चौधरी	खगड़िया	स्व० हरिकान्त प्रसाद सिंह, जे०पी०एन० लेन, पूर्वी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार, पिन-800003	सामान्य	मंडल कारा, सुपौल
13	डॉ० अनिल कुमार	श्री शिवशंकर प्रसाद	प० चम्पारण	ग्राम-कालीबाग, न्यू कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, प्रो०+प्रखण्ड-बेतिया, जिला-पश्चिमी चम्पारण	पि०वर्ग	उपकारा, बगहा
14	डॉ० नितीन कुमार	डॉ० सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह	नालंदा	ग्राम- कागजी मुहल्ला, पुरानी जेल रोड, बिहारशरीफ (नालन्दा)-803101	सामान्य	मुक्त कारागार, बक्सर
15	डॉ० शिवानी गुप्ता	डॉ० एस०पी० गुप्ता	प० चम्पारण	हास्पिटल रोड, बेतिया, प० चम्पारण-845438	सामान्य (महिला)	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी
16	डॉ० शशिभूषण कुमार	श्री मनोज प्रसाद सिंह	पटना	फ्लैट नं०-105, अनिसाबाद, शिवपुरी चौक, बेऊर, पटना-800002	पि०वर्ग	मंडल कारा, लखीसराय
17	डॉ० बिपिन बिहारी शरण	स्व० विश्वनाथ गराई	नालंदा	ग्राम-उत्तरनावी, पोस्ट-उत्तरनामा, थाना-रहुई, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-803119	पि०वर्ग	मंडल कारा, शेखपुरा
18	डॉ० रफत परवीन	श्री सैयद नसीम अहमद	पटना	खगौल, पटना बिहार	सामान्य (महिला)	उपकारा, हिलसा
19	डॉ० कुमार राहुल	श्री अरविन्द कुमार जायसवाल	वैशाली	ड्रग इंटरप्राइजेज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, पो०- महुआ, जिला- वैशाली	पि०वर्ग	मंडल कारा, सीतामढ़ी
20	डॉ० बुलबुल कुमारी	श्री उमाकान्त चौधरी	बेगूसराय	ग्राम- साठा, पो०- रसीदपुर, जिला-बेगूसराय-851128	सामान्य (महिला)	उपकारा, दलसिंहसराय
21	डॉ० ज्योति रश्मि	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा	गया	ग्राम-सूरजू बिगहा, पो०-हेमारा, खिजरसराय, जिला-गया	सामान्य (महिला)	उपकारा, शेरघाटी
22	डॉ० डिम्पल	श्री मनीष कुमार	नवादा	फ्लैट नं०-14, जमुना अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड, पटना, बिहार, पिन-800013	पि०वर्ग (महिला)	शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर
23	डॉ० प्राची प्रिया	श्री अशोक प्रसाद सिंह	पटना	चुहरमल नगर, फुलवारीशरीफ, पटना	सामान्य (महिला)	शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर
24	डॉ० देव प्रकाश	श्री सुरेश प्रसाद	पटना	विकाश बिहार कॉलोनी, उफरपुरा, पटना एयरपोर्ट के पश्चिम, पटना, पिन-801506	अनु०जाति	केन्द्रीय कारा, पुर्णियाँ
25	डॉ० बलबिन्दर कुमार	श्री कृष्णा राम	सिवान	ग्राम-फुलवरिया, पोस्ट-करसर थाना-रघुनाथपुर, जिला-सिवान बिहार, 841504	अनु०जाति	मंडल कारा, गोपालगंज
26	डॉ० प्रवीण कुमार सिंह	श्री चन्द्रेश्वर सिंह	रोहतास	ग्राम-सिरिसियाँ, पो०-करगहर, सासाराम	पि०वर्ग	मंडल कारा, सासाराम
27	डॉ० रुपेश चन्द्र	श्री बाबूलाल ठाकुर	मोतिहारी	ग्राम-छतौनी, नियर स्पोर्ट्स क्लब, मोतिहारी	अनु०जाति	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी
28	डॉ० संजीव कुमार	श्री यमुना प्रसाद	नालंदा	ग्राम+पो०+थाना- वेना, जिला- नालन्दा, 803110	पि०वर्ग	मंडल कारा, जमुई

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता (पिन कोड सहित)	आरक्षण कोटि (वास्तविक)	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
29	डॉ० दीपक कुमार	श्री रामदेव यादव	पटना	ग्राम-श्रीनगर, थाना- मसौढ़ी, जिला- पटना-804452	पि०वर्ग	मंडल कारा, किशनगंज
30	डॉ० जितेन्द्र काजी	श्री विश्वनाथ काजी	प० चम्पारण	ग्राम-बैरियाखुर्द, पोस्ट-हरनाटांड थाना-सौकरिया, जिला-प० चम्पारण, बिहार, पिन-845105	अनु० जन जाति	उपकारा, बिक्रमगंज
31	डॉ० ज्ञानी गौरव कुमार	श्री नीलम संजीव कुमार	नालंदा	ग्राम+पो०-कछियावाँ, थाना-नगरनौसा, जिला-नालंदा-801302	अनु०जाति	मंडल कारा, नवादा
32	डॉ० विकास पासवान	स्व० अर्जुन पासवान	मधेपुरा	ग्राम+पो०- बजराहा, थाना- आलमनगर, जिला-मधेपुरा 852219	अनु०जाति	मंडल कारा, मधेपुरा
33	डॉ० अमरेश कुमार	श्री विश्वेसर साह	वैशाली	ग्राम- भरहो, पो०- सरमस्तपुर, वैशाली-844501	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, समस्तीपुर
34	डॉ० शरत रंजन	श्री देवनारायण वर्मा	पटना	ग्राम/ मो०-न्यू कॉलनी गोरैया, स्थान-चौकशिकारपुर, पटना सिटी, पोस्ट-बेगमपुर, बिहार, पिन-800009	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, मधेपुरा
35	डॉ० उदय कुमार	श्री जगदीश पासवान	अरवल	ग्राम-अबगिला, पो०-सरवाँ, जिला- अरवल-804402	अनु०जाति	उपकारा, बक्सर
36	डॉ० शशिकांत कुमार	श्री रामजी राय	औरंगाबाद	ग्राम-मल्लाह टोली, पो०+थाना-देव, जिला-औरंगाबाद-824202	अनु०जाति	मंडल कारा, औरंगाबाद
37	डॉ० भूपेन्द्र कुमार मंडल	स्व० शितलाल मंडल	अररिया	ग्राम-पलासमनी, पो०+थाना-सिकटी, जिला-अररिया 854333	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, अररिया
38	डॉ० सुभाष	श्री अवधेश चौधरी	औरंगाबाद	ग्राम-बधन बिगहा, पोस्ट-तरार, जिला-औरंगाबाद, बिहार, पिन-824113	अनु०जाति	मंडल कारा, औरंगाबाद
39	डॉ० कृष्ण चन्द	श्री राम नरेश रजक	अरवल	ग्राम-परियारी, पोस्ट-किंजर, प्रखंड-करपी, जिला-अरवल, बिहार, पिन-804426	अनु०जाति	मंडल कारा, नवादा
40	डॉ० अरुण कुमार	श्री रामस्वरूप राम	गया	ग्राम-रेवाड़ा, पो०-चाकन्द, जिला-गया-804404	अनु०जाति	उपकारा, बक्सर
41	डॉ० अखिलेश कुमार भारती (PH)	श्री शंकर प्रसाद	समस्तीपुर	ग्राम+पो०-कापन, थाना-विभूतिपुर, रोसड़ा समस्तीपुर	पि०वर्ग	उपकारा, रोसड़ा
42	डॉ० प्रमोद कुमार	श्री शिवराम महतो	लखीसराय	ग्राम-खावाचन्द्र टोला किरणपुर, लखीसराय 811106	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, मुंगेर
43	डॉ० सत्येन्द्र कुमार सत्या	श्री पचकौड़ी राम	मधुबनी	ग्राम-नवनगर, पो०+थाना-रुद्रपुर, प्रखण्ड-अंधाराखाड़ी झेझारपुर, मधुबनी	अनु०जाति	मंडल कारा, सहरसा
44	डॉ० चौधरी रवि राम	श्री अरिमर्दन चौधरी	भोजपुर	पश्चिमी जगदेवनगर, चन्द्रमा मार्केट के समीप आरा, जिला-भोजपुर-802302	अनु०जाति	केन्द्रीय कारा, बक्सर
45	डॉ० संजीव कुमार	श्री बटेश्वर प्रसाद दास	बाँका	ग्राम+पोस्ट+थाना-अमरपुर जिला-बाँका, बिहार, 813101	अनु०जाति	उपकारा, नवगछिया
46	डॉ० संदीप कुमार भारती	श्री मोतीलाल ठाकुर	भागलपुर	ग्राम-हसनगंज, पो०-मिरजान हाट, भागलपुर	अ०पि०वर्ग	मंडल कारा, बाँका

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता (पिन कोड सहित)	आरक्षण कोटि (वास्तविक)	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
47	डॉ० विकाश कुमार (PH)	श्री रुदल रजक	वैशाली	ग्राम-बागमली, पोस्ट-हाजीपुर, जिला-वैशाली	अनु०जाति	मंडल कारा, शेखपुरा

3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में पंद्रह दिनों के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के अंतर्गत योगदान नहीं करने वाले चिकित्सकों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

13 जून 2017

सं० कारा/स्था० (चि०)01-03/2017-3009—राज्य की काराओं में पदस्थापित निम्नांकित संविदा आधारित चिकित्सकों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कारा में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापित कारा का नाम	नया पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	डॉ० आशीष डी० सिन्हा	सारण	उपकारा, दानापुर	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना।
2	डॉ० मो० अफताब आलाम	जमुई	मंडल कारा, जमुई	मंडल कारा, लखीसराय
3	डॉ० दयानंद सिंह	सीवान	मंडल कारा, गोपालगंज	मंडल कारा, सीवान

4. सभी चिकित्सकों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में स्थानांतरित संविदा आधारित चिकित्सकों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें तुरन्त विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

### परिवहन विभाग

#### आदेश

13 जून 2017

सं० 05/स्था० (डी.टी.ओ)-30/2013-3095— परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला/चेक पोस्ट पर तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोज कुमार शाही, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोपालगंज	अररिया	पूर्णिया तथा किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार)
2.	श्री अब्दुल रज्जाक, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोड्डा (झारखंड)	खगड़िया	मधेपुरा
3.	श्री माधव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	औरंगाबाद	भोजपुर (आरा)	रोहतास (अतिरिक्त प्रभार)

क्र०सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
4.	श्री अरुण कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	रोहतास	सुपौल	अररिया (अतिरिक्त प्रभार)
5.	श्री भुपेन्द्र यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी	पू० चम्पारण	गोपालगंज	बलथरी चेक पोस्ट (अतिरिक्त प्रभार)
6.	श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	भोजपुर	नवादा	रजौली चेक पोस्ट (अतिरिक्त प्रभार)
7.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी	गया	जमुई	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) तथा प० चम्पारण (अतिरिक्त प्रभार)
8.	श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी	किशनगंज	मुंगेर	मुजफ्फरपुर
9.	श्री आलोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	नवादा	मुजफ्फरपुर	मुंगेर
10.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	नालन्दा	सिवान	शिवहर
11.	श्री भरत भुषण प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	पटना	कैमूर (भभुआ) रोहतास अतिरिक्त प्रभार	कैमूर (भभुआ)
12.	श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी	गाजीपुर (उ०प्रदेश)	मधेपुरा	सारण (छपरा)
13.	श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	खगड़िया	मोतिहारी (पू० चम्पारण)	जमुई
14.	श्री विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधेपुरा	दरभंगा	अरवल
15.	श्री चितरंजन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधुबनी	शिवहर/सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
16.	श्री लाल बाबु सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	पू० चम्पारण	समस्तीपुर	दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार)
17.	श्री कृष्ण मोहन सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	पटना	पूर्णियाँ	सिवान
18.	श्री पुरुषोत्तम, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी	नालन्दा	पटना	खगड़िया

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3 उपरोक्त जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नव पदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, अपर सचिव।

निगरानी विभाग  
सूचना भवन, पटना।

अधिसूचना  
23 जून 2017

सं० परि० कार्मिक-53/2016-2662(अनु०)—जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-119 (प्र०)/सी० दिनांक 17.05.2017 एवं गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-4744 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में श्री कुमार अनुज, बि०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) बागबाड़ी, भागलपुर एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी मोजाहिदपुर (बबरगंज) थाना कांड संख्या-89/17 दिनांक 02.05.2017 के अग्रेतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को ग्रहण करने का आदेश पारित किया गया है।

अतः तत्कालिक प्रभाव से मोजाहिदपुर (बबरगंज) थाना कांड संख्या-89/17 दिनांक 02.05.2017 के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

परिवहन विभाग

शुद्धि-पत्र

14 जून 2017

सं० 05/स्था० (डी.टी.ओ.)-30/2013-3135—परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित निर्गत आदेश संख्या-3095 दिनांक 13.06.2017 में 'आदेश' के स्थान पर 'अधिसूचना' पढ़ा जाय। साथ ही, उक्त अधिसूचना बिहार राज्यपाल के आदेश से निर्गत समझी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं  
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

---

सूचना

---

No 760— I, Affidavit no. 15950 Dated 02-05-2017 के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं RITA KUMARI पिता राम दुलार पांडेय, पति—राजीव रंजन पांडेय के०जी० रोड नवादा, आरा (बिहार) की निवासी हूँ। शादी के पहले मेरा नाम RITA KUMARI था शादी के बाद मेरा नाम Rita Pandey है। मैं Rita Pandey के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ।

RITA KUMARI .

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 08/आरोप-01-62/2016, सां०प्र०-6401

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 मई 2017

श्री नरेश द्विवेदी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1335/85, 817/91 (सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध उपायुक्त चाईबासा को षड्यंत्रपूर्वक रिश्त देने का प्रयास करने के आरोप में चाईबासा मुफरिसल थाना कांड सं०-14/1991 दिनांक 15.02.1991 दर्ज हुआ। इस क्रम में विभागीय आदेश सं०-4220 दिनांक 25.03.1991 द्वारा श्री द्विवेदी निलंबित हुए एवं कालान्तर में आदेश ज्ञापांक-8683 दिनांक 16.08.1996 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। श्री द्विवेदी के दिनांक 30.06.1996 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11423 दिनांक 17.10.1996 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में पत्रांक-7995 दिनांक 22.07.1998 द्वारा दंड स्वरूप 25 प्रतिशत पेंशन कटौती का आदेश संसूचित किया गया।

श्री द्विवेदी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले (मुफरिसल थाना, चाईबासा कांड सं०-14/1991 दिनांक 15.02.1991) से उद्भूत विशेष वाद सं०-06/91 में विशेष न्यायाधीश (झारखंड निगरानी ब्यूरो) द्वारा दिनांक 30.06.2014 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा श्री द्विवेदी एवं अन्य दो आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसी आलोक में श्री द्विवेदी ने महामहिम राज्यपाल, बिहार को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए पेंशन कटौती आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। उक्त अपील अभ्यावेदन की प्रति राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1816 दिनांक 14.12.2016 द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री द्विवेदी का एक अभ्यावेदन (दिनांक 27.02.2017) भी सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने पेंशन कटौती संबंधी संसूचित दंड निरस्त करने का अनुरोध किया।

श्री द्विवेदी के अपील अभ्यावेदन एवं उपलब्ध अभिलेख की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि भ्रष्टाचार के संदर्भित आरोपों पर न्यायिक एवं विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से अलग-अलग संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर इन्हें दंड संसूचित किया गया। श्री द्विवेदी ने उक्त दंड पर बचाव के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया तथा केवल न्यायिक कार्यवाही में दोष मुक्त किये जाने के आधार पर पेंशन जब्त करने संबंधी आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। वस्तुतः निगरानी न्यायालय द्वारा उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है तथा दोनों प्रक्रिया (न्यायिक एवं विभागीय कार्यवाही) अलग-अलग संचालित हुए। ऐसी स्थिति में श्री द्विवेदी का अपील अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री नरेश द्विवेदी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1335/85, 817/91 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पेंशन से 25 प्रतिशत कटौती संबंधी संसूचित दंड को यथावत् रखा जाता है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-101/2014, सा०प्र०-6402

#### संकल्प

29 मई 2017

श्री नसीब लाल दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-681/11 के प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के पदस्थापन काल में पंचायत शिक्षको की नियुक्ति से संबंधित मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर हुआ। उक्त रीट याचिका से उद्भूत अवमाननावाद संख्या-2679/2009 में पारित आदेश (दिनांक 05.01.2011) में प्रतिवादी संख्या-4 (श्री नसीब लाल, दास) के कार्यकलाप पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-392 दिनांक 17.02.2011 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया। इस क्रम में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा श्री दास के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निदेश प्राप्त हुआ।

तदुपरांत विभागीय पत्रांक 3003 दिनांक 15.03.2011 एवं अनुवर्ती स्मारों द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से आरोप, प्रपत्र की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी से आरोप, प्रपत्र-‘क’ अप्राप्त रहने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेख/आरोपों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-11587 दिनांक 10.08.2015 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस क्रम में श्री दास से स्पष्टीकरण (दिनांक 15.02.2016) प्राप्त हुआ। समीक्षोपरांत विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र-‘क’ की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13838 दिनांक 06.10.2016 श्री दास से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री दास ने इस क्रम में समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक 08.11.2016) में उल्लेख किया कि पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-12975/2007 में पारित आदेश (दिनांक 24.03.2009) के अनुपालन में की गयी कार्रवाई से संबंधित तथ्य सरकारी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अवमाननावाद का संज्ञान होते ही उनके द्वारा त्वारित कार्रवाई की गयी, जिसके आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा अग्रेतर कार्रवाई समाप्त कर दी गयी।

आरोप, प्रपत्र ‘क’ एवं श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि आरोपों पर बचाव के क्रम में श्री दास द्वारा न्यायादेश की प्रति प्राप्त होने, जिला स्तर से इसका अनुपालन किये जाने एवं सरकारी अधिवक्ता को तथ्य विवरणी भेजे जाने इत्यादि के संबंध में तिथिवार धटनाक्रम एवं स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। वस्तुतः श्री दास एवं संबंधित सरकारी अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के बीच समन्वय का अभाव रहा। जिसके फलस्वरूप अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई। इस परिप्रेक्ष्य में श्री दास के कर्तव्य में चूक का तथ्य प्रमाणित पाया गया एवं स्पष्टीकरण अस्पष्ट होने के साथ ही स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री नसीब लाल दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-681/11 को निम्नलिखित शास्ति संसूचित की जाती है:-

(क) निन्दन (आरोप वर्ष 2009-10 के प्रभाव से)।

(ख) प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (प्रोन्नति देयता तिथि से)।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 2/सी०-10161/2006-सा०प्र०-4492

#### संकल्प

13 अप्रैल 2017

श्री अजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 437/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी -सह-निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), रजौली, नवादा के विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, मतगणना में धांधली, अनियमितता एवं हेरा-फेरी, शील निष्ठा की कमी, बिहार पंचायत राज अधिनियम की अनदेखी, अनुशासनहीनता, सरकारी सेवक के विपरीत आचरण हड़ताल और

प्रदर्शन करना, उच्चतर पदाधिकारी पर बचाव हेतु राजनीतिक एवं बाहरी दबाव बनाने की कोशिश करना, मतगणना में किये गये हेरा-फेरी के कार्य एवं अनैतिक आचरण को प्रतिसमर्थित करने का प्रयास करना एवं मतगणना कार्य में हेरा-फेरी करने आदि का आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11127 दिनांक 11.08.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 43 दिनांक 12.01.2017 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि स्व० अजय कुमार की मृत्यु दिनांक 11.09.2016 को हो चुकी है, जो स्व० कुमार के मृत्यु प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है।

आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 693 दिनांक 01.03.2017 द्वारा स्व० अजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 437/11 की मृत्यु दिनांक 11.09.2016 को हो जाने के आधार पर स्व० अजय कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11127 दिनांक 11.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही की सुनवाई समाप्त किये जाने की सूचना दी गयी।

वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय पत्रांक 3422 दिनांक 28.03.1990 में निहित निदेश के आलोक में स्व० अजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 437/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), रजौली, नवादा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11127 दिनांक 11.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार स्व० अजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 437/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), रजौली, नवादा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11127 दिनांक 11.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

**आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,  
**भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।**

सं० 2/सी०-10102/2009-सा०प्र०-5835

#### संकल्प

16 मई 2017

श्रीमती इन्दू कुमारी (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1188/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 9359 दिनांक 16.08.2010 द्वारा इंदिरा आवास के लिए संधारित पंजी को सत्यापित नहीं करने, पंजी में की गयी प्रविष्टि के उपरान्त हस्ताक्षर नहीं करने, योजना पंजी में कतिपय मामलों में लाभार्थियों का नाम अंकित नहीं रहने, लछनौता पंचायत में प्रतीक्षा सूची के क्रमांक को तोड़कर इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने से संबंधित आरोप के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

इसी बीच ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 2832 दिनांक 14.03.2011 द्वारा श्रीमती इन्दू के विरुद्ध साक्ष्यों सहित पूरक आरोप-पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध इंदिरा आवास, के०सी०सी० एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना में अवैध राशि लेने, इंदिरा आवास योजना में राशि भुगतान हेतु लाभार्थियों का एडभाईस किस्त करके एवं क्रम तोड़कर बैंकों को भेजने एवं इनके पति के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक 9155 दिनांक 16.09.2010 एवं पत्रांक 5088 दिनांक 06.05.2011 द्वारा श्रीमती इन्दू को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। स्मारित किये जाने के बावजूद भी स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 120 दिनांक 05.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2511/भी० दिनांक 14.10.2015 द्वारा श्रीमती इन्दू के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-01(4) को मुख्यतः अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-01(च) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 12468 दिनांक 12.09.2016 द्वारा असहमति के बिन्दुओं पर श्रीमती इन्दू से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

5. श्रीमती इन्दू के पत्र दिनांक 18.10.2016 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा संबंधित पंजियों पर हस्ताक्षर आरोपों का गठन हो जाने के पश्चात् तथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् किया गया है। श्रीमती इन्दू कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में से इंदिरा आवास योजना के योजना पंजी को विधिवत् संधारित नहीं करने एवं की गयी प्रविष्टियों के उपरान्त हस्ताक्षर नहीं करने/सत्यापित नहीं करने का आरोप, आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न साक्ष्यों के आधार पर स्वतः प्रमाणित है।

6. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती इन्दू कुमारी (बि०प्र०से०) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17128 दिनांक 26.12.2016 द्वारा "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

7. उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्रीमती इन्दू के पत्र दिनांक 10.02.2017 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनका कहना है कि आरोप-पत्र गठन के समय वे मधुबनी जिला में कार्यरत थी और ऐसी स्थिति में गौनाहा प्रखंड जाकर इंदिरा आवास के पंजी पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं थी। उक्त आधार पर इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दण्ड मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

8. श्रीमती इन्दू द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्रीमती इन्दू द्वारा कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि इस पर विचार किया जा सके। उनके द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो इनके द्वारा पूर्व में कहा गया था।

10. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती इन्दू कुमारी (बि0प्र0से0) के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17128 दिनांक 26.12.2016 द्वारा "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

11. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती इन्दू कुमारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1188/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17128 दिनांक 26.12.2016 द्वारा "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 2/आरोप-01-07/2017-सा0प्र0-6431

#### संकल्प 30 मई 2017

श्री मदन कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 904/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा के विरुद्ध दिनांक 14.01.2017 को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना की जाँच उच्च स्तरीय द्वि-सदस्यीय जाँच समिति द्वारा करायी गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को गंभीर प्रशासनिक चूक एवं विधि व्यवस्था में लापरवाही का दोषी पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2292 दिनांक 24.02.2017 द्वारा निलंबित किया गया।

2. समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। श्री कुमार से उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक 3356 दिनांक 21.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं पत्रांक 4639 दिनांक 20.04.2017 द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरुद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाता है, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. जिला पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को देंगे।

5. श्री मदन कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 904/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 2/आरोप-01-23/2014-सा0प्र0-6813

संकल्प

6 जून 2017

श्री अरविन्द कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-572/11, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 716 दिनांक 08.03.2014 द्वारा प्रपत्र 'क' एवं पत्रांक 1105 दिनांक 15.04.2014 द्वारा संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ। उक्त आरोप-पत्र में श्री झा के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-10/09 दिनांक 06.02.09 के प्राथमिकी अभियुक्त, श्री हरिशंकर प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच एवं सुनवाई कर आरोप की प्रामाणिकता पर मन्तव्य सहित जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने, स्थानान्तरण होने पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, प०चम्पारण, बेतिया के पद पर योगदान करने के बावजूद संचालित विभागीय कार्यवाही का अभिलेख स्थापना शाखा को वापस नहीं करने, इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों के आधार पर स्वतः खण्डन होने, महत्वपूर्ण विभागीय कार्यवाही के अभिलेख के रख-रखाव में लापरवाही बरतने का आरोप है।

2. विभागीय पत्रांक 7494 दिनांक 04.06.14 द्वारा श्री झा से प्रतिवेदित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् पत्रांक 14041 दिनांक 14.10.14, 18075 दिनांक 31.12.14, 7150 दिनांक 15.05.15 एवं पत्रांक 204 दिनांक 06.01.16 द्वारा श्री झा को स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। किन्तु श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. प्रासंगिक मामले की समीक्षा के उपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7045 दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 185 दिनांक 19.01.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अंकित है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण में आरोपित पदाधिकारी श्री झा द्वारा कहा गया है कि उन्हें श्री हरिशंकर प्रसाद, हल्का कर्मचारी, अंचल कार्यालय, लक्ष्मीपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। इससे संबंधित आदेश ज्ञापांक 482, दिनांक 23.09.2009 को प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने पूरी तत्परता से इस विभागीय कार्यवाही अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेवारी उस वक्त राजस्व शाखा के ही एक लिपिक श्री रूपेश कुमार झा को सौंपते हुए आरोपी कर्मियों के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया ताकि वे गठित आरोप से बचाव हेतु साक्ष्यों पर आधारित अपना पक्ष मेरे समक्ष रख सकें। उन्होंने सुनवाई के लिए दिनांक 16.11.2009 की तिथि भी निर्धारित किया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त संबंधित राजस्व कर्मचारी श्री हरिशंकर प्रसाद के द्वारा निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब दाखिल करने हेतु निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक एस0आर0-010/2009/नि0-225/अ0प0 शाखा, दिनांक 11.02.2009 की एक प्रति की मांग की गई। इस वांछित कागजात को उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने इस विभागीय कार्यवाही अभिलेख को संधारित करने हेतु जिम्मेवार लिपिक श्री रूपेश कुमार झा, राजस्व शाखा को जिला स्थापना शाखा से सम्पर्क करने का मौखिक निर्देश दिया ताकि अगली तिथि तक वांछित साक्ष्य/कागजात निलंबित राजस्व कर्मचारी को उपलब्ध कराया जा सके। इस वाद अभिलेख में निर्धारित अगली तिथि दिनांक 07.01.2010 को पुनः आरोपी कर्मियों श्री हरिशंकर प्रसाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पुनः उसी कागजात की मांग की, लेकिन जिला स्थापना शाखा के द्वारा वह कागजात उस दौरान उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह सिलसिला अगले एक-दो तिथियों तक आगे भी चला और उसके बाद जिलाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 615 दिनांक 08.04.2010 के माध्यम से उन्हें प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा के कार्य बोझ से मुक्त करते हुए यह जिम्मेवारी श्री भूपेन्द्र यादव, वरीय उप समाहर्ता, जमुई को सौंप दी गई। चूँकि इस विभागीय कार्यवाही के संचालन की जिम्मेवारी उन्हें प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा के रूप में ही सौंपी गई थी और जब वे इस शाखा के प्रभार में ही नहीं रहे, तब इस विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करना अब उनके प्रतिस्थानी का दायित्व है। यह विश्वास उनके मन में तब धीरे-धीरे और पक्का हो गया जब राजस्व शाखा का प्रभार सौंपने के उपरान्त इस विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख के संधारणकर्ता (कस्टोडियन) लिपिक श्री रूपेश कुमार झा के द्वारा वर्ष 2013 में उनके बेतिया स्थानान्तरण तक कभी न तो वह अभिलेख ही उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही उसकी प्रगति के संबंध में उन्हें कोई जानकारी ही दी गई। उन्हें बेतिया में योगदान करने हेतु गोपनीय शाखा, जमुई के द्वारा ही पत्र संख्या-791 दिनांक 06.07.2013 से विरमित किया गया। इनका यह भी कहना है कि जब तक वे राजस्व शाखा के प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे, उस समय तक संदर्भित विभागीय कार्यवाही के अभिलेख के कस्टोडियन के रूप में राजस्व शाखा का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंप दिया तो उसके लगभग तीन वर्षों के बाद तक वे जमुई जिले में ही अपने मूल अधिसूचित उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहे, लेकिन दिनांक 07.11.2011 के पश्चात् न तो मौखिक रूप से, न ही लिखित तौर पर विभागीय कार्यवाही के अभिलेख अथवा इससे संबंधित रिपोर्ट के लिए कभी भी उनसे मांग की गई। ऐसी स्थिति में वे पूरी तरह आश्वस्त हो गये कि जिला स्थापना शाखा के द्वारा उन्हें दी गई जानकारी ही वास्तविक है, जिसके अनुसार श्री हरिशंकर प्रसाद आरोपी कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच रिपोर्ट एवं अभिलेख सौंपने की जिम्मेवारी अब उनके प्रतिस्थानी की थी।

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के उपर्युक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य प्रतिवेदित किया गया।

5. प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मन्तव्य के आलोक में श्री झा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7045 दिनांक 17.05.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरविन्द कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-572/11, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7045 दिनांक 17.05.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

2/आरोप- 01-38/2014 -सा0प्र0- 6814

### संकल्प

6 जून 2017

श्री मुकेश कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1141/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज, अररिया सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 282 दिनांक 10.06.2014 द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 1294/11-12 के आदेश दिनांक 19.08.2011 के विरुद्ध अपील आवेदन दिनांक 16.03.2012 का निपटारा गैर जिम्मेदारीपूर्वक करने के आरोपों के लिए गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा को विभागीय पत्रांक 9864 दिनांक 18.07.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री सिन्हा के पत्र दिनांक 12.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी आरोपों से इंकार किया गया है।

3. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 12018 दिनांक 29.08.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1978 दिनांक 10.11.2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरुद्ध गठित सभी आरोपों के संदर्भ में उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं होने का मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

4. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17239 दिनांक 15.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. प्रमंडलीय आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के पत्रांक 1977 दिनांक 06.05.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा सभी पाँच आरोपों के संदर्भ में मंतव्य गठित किया गया है, जिसमें आरोप संख्या-01, 02, 03 एवं 05 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-04 को अंशतः प्रमाणित माना गया है।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर आरोप संख्या-04 में अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 12368 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री सिन्हा से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री सिन्हा के अभ्यावेदन दिनांक 26.09.2016 द्वारा आरोप संख्या-04 के संदर्भ में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा आरोप-पत्र दिनांक 11.03.2014 को गठित किया गया है, जबकि उससे सात (07) माह पूर्व ही अपीलार्थी के नकल चिरकूट संख्या-1165 दिनांक 14.06.2013 के आलोक में अपीलार्थी को संबंधित नकल अनुमंडल अभिलेखागार द्वारा दिनांक 31.07.2013 को उपलब्ध करा दिया गया था। श्री सिन्हा का यह भी कहना है कि आवेदक के द्वारा चिरकूट दाखिल किए जाने पर बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के प्रावधानों के अनुसार नकल निर्गत करने हेतु अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी जवाबदेह होते हैं। अनुमंडल कार्यालय, फारबिसगंज के अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, फारबिसगंज थे। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल नकल चिरकूट के उपर अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है और निर्गत करने वाले पंजी में प्रधान सहायक का हस्ताक्षर है। श्री सिन्हा का यह भी कहना है कि निर्गत किए जाने वाले नकल के चिरकूट पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर केवल इस आशय से होता है कि यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो नकल दिया जाय और वह भी तब जब अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी किसी कारणवश उस दिन उपलब्ध न हों।

7. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 26.09.2016 को अस्वीकृत करते हुए अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत "निन्दन (आरोप वर्ष 2013-14) एवं एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।



8. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1141/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारविसगंज, अररिया सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 प्रावधानों के तहत “निन्दन (आरोप वर्ष 2013-14) एवं एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 2/आरोप-01-07/2015-सा0प्र0-6811

#### संकल्प

6 जून 2017

श्री देवेन्द्र प्रसाद, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-308/2011, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ साक्ष्य सहित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक 262 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र में डॉ० सुभाष कुमार, तत्कालीन भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी, जैतपुर, मुजफ्फरपुर के निलंबन से विमुक्ति संबंधी प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव नहीं दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रपत्र ‘क’ के आरोपों के लिए श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 16.03.2015 समर्पित किया गया। आरोप-पत्र के आरोपों एवं श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9682 दिनांक 06.07.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. ज्ञापांक 513 दिनांक 08.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित निष्कर्ष प्राप्त हुआ। उक्त निष्कर्ष में श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. प्रमाणित आरोप के लिए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 16625 दिनांक 01.12.2015 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 17.03.2016 समर्पित किया गया।

5. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष, श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संचिका में उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, लेकिन श्री प्रसाद द्वारा आरोप-पत्र में वर्णित डॉ० सुभाष कुमार, तत्कालीन भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी, जैतपुर के निलम्बन मुक्ति से संबंधित प्रस्ताव माननीय मंत्री के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किये जाने का स्पष्ट प्रस्ताव नहीं देने संबंधी आरोप को दृष्टि चूक स्वीकार किया गया है।

6. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधान के तहत श्री प्रसाद के “पेंशन से 10% राशि की कटौती दो वर्षों तक” करने का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. विभागीय पत्रांक-11691 दिनांक 30.08.2016 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2139 दिनांक 19.10.2016 द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

8. प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15431 दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-308/11 तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के संगत प्रावधान के तहत “पेंशन से 10% राशि की कटौती दो वर्षों तक” करने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

9. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15431 दिनांक 16.11.2016 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 26.12.2016 समर्पित किया गया।

उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में श्री प्रसाद का कहना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15431 दिनांक 16.11.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43‘बी’ के संगत प्रावधान के अन्तर्गत ‘पेंशन से 10% राशि की कटौती दो वर्षों तक करने’ का दंड अधिरोपित किया गया है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43‘बी’ के अन्तर्गत पेंशन की कटौती तब ही की जायेगी, जब वित्तीय अनियमितता अथवा सरकारी राशि का गबन संबंधी आरोप प्रमाणित होता है। डॉ० सुभाष कुमार, तत्कालीन पशु चिकित्सा, जैतपुर के निलम्बन मुक्ति से संबंधी प्रस्ताव मा० मंत्री के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किये जाने का स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया जाने संबंधी दृष्टि चूक के लिए उपर्युक्त शास्ति बहुत बड़ी सजा है, जबकि सरकार को कोई क्षति नहीं पहुँची है। उक्त आधार पर श्री प्रसाद द्वारा अधिरोपित शास्ति को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

10. प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रसाद के विरुद्ध दंड संसूचित किया गया है। साथ ही श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में भी किया गया था।

11. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15431 दिनांक 16.11.2016 द्वारा संसूचित दंड को पूर्ववत बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

12. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15431 दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-308/2011, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के संगत प्रावधान के तहत अधिरोपित एवं संसूचित "पेंशन से 10% राशि की कटौती दो वर्षों तक" करने के दंड को पूर्ववत बरकरार रखा जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार —राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 2/नि0था0-11-14/2012 —सा0प्र0-5556

#### संकल्प

9 मई 2017

श्री इम्तियाज अहमद करीमी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 571/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर सम्प्रति निदेशक (उर्दू) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में यथा-शिक्षामित्र की नियुक्ति, विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय झूगरी-झोपड़ी छिहत्तर का चुनाव, बाढ़ राहत, इंदिरा आवास आदि में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए निगरानी थाना कांड संख्या 57/2009, मनेर में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 77 दिनांक 28.02.2014 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

2. विभागीय पत्रांक 12414 दिनांक 05.09.2014 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में श्री करीमी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री करीमी के पत्र दिनांक 17.10.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17567 दिनांक 19.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. इसी बीच पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 162/अप0शा0 दिनांक 29.01.2015 द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी थाना कांड सं० 57/09 में श्री इम्तियाज अहमद करीमी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनेर, जिला पटना को दोषमुक्त करते हुये शेष प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया गया है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के उपर्युक्त पत्र के आलोक में श्री करीमी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन द्वारा विभागीय कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृत्यादेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रासंगिक मामले से संबंधित तथ्यों के आलोक में विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी। उक्त के संदर्भ में विधि विभाग का परामर्श निम्नवत् है :-

"वर्तमान में चूंकि अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्राथमिक अभियुक्त श्री करीमी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, बिना आरोप पत्र के न्यायालय में श्री करीमी के विरुद्ध अभियोजन नहीं चल सकता है। जबतक कि न्यायालय स्वयं अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम दृष्टया संतुष्ट न हो जाय।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत अभियोजन रद्द करने का क्षेत्राधिकार, उसे निर्गत करने वाले विभाग को भी नहीं है और चूंकि श्री करीमी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जारी अभियोजन स्वीकृत्यादेश स्वमेव अप्रभावी हो जाता है और उसे वापस या रद्द करने का कोई प्रावधान एवं आवश्यकता नहीं है।"

5. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त (विभागीय जाँच), पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1380 दिनांक 12.09.2015 द्वारा श्री करीमी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नांकित निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

"आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8911 दिनांक 19.06.2015 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप या तो उनके पदस्थापन अवधि के पूर्व का है या पदस्थापन अवधि के बाद का है। साथ ही पूर्णतः पंचायत के योजना से संबंधित है। इंदिरा आवास योजना सं०-04/2004-05, 05/2004-05 एवं 02/2004-05 में आवास की स्वीकृति आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। उक्त तीनों योजना में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को पंचायत सचिव के अनुशंसा पर चेक के माध्यम से मो० 12,500.

00 का भुगतान किया गया है। इंदिरा आवास मार्ग निर्देशिका के अध्याय 11 के कंडिका 2.4 के अनुसार आवास निर्माण का उत्तरदायित्व लाभार्थी का होता है। लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त लेकर मकान नहीं बनाने के कारण लाभार्थी को दूसरे किस्त का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह आरोपी पदाधिकारी द्वारा इंदिरा आवास चयन/निर्माण संबंधी मार्ग निर्देशिका का अनुपालन किया गया है। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है। जिसकी पुष्टि निगरानी विभाग के पत्रांक 162 दिनांक 29.01.2015 से भी होती है। निगरानी थाना कांड सं0-57/2009 में आरोपी पदाधिकारी को अनुसंधान के क्रम में दोष मुक्त पाया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी को छोड़कर शेष अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पत्र सं0-107/2014 दिनांक 16.11.2014 समर्पित किया गया है।”

6. अनुशासनिक प्राधिकर द्वारा श्री करीमी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, निगरानी विभाग के पत्रांक 162 दिनांक 29.01.2015 एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से श्री करीमी के विरुद्ध समर्पित अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का आधार, बाद में अनुसंधान कर दोषमुक्त किये जाने का आधार एवं श्री करीमी को अभियुक्त बनाये जाने के आधार के संबंध में विभागीय पत्रांक 2390 दिनांक 16.02.2016, 8107 दिनांक 06.06.2016 एवं 1392 दिनांक 06.02.2017 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 829 दिनांक 31.03.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में उक्त पृच्छा की बिन्दुवार विवरणी उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नवत् है :-

(क) श्री रामाधार सिंह परिवारी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में दायर नालसी वाद सं0-15/2006 में माननीय विशेष न्यायालय, पटना द्वारा परिवाद के जाँच हेतु परिवाद-पत्र को ज्ञापांक 140 दिनांक 17.10.2006 के द्वारा निगरानी थाना भेजा गया, जिसे जाँच सं0-डी0/09/06/का0 पटना नि0 686/जाँच दिनांक 14.11.2006 द्वारा पंजीकृत कर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक निगरानी को जाँच का प्रभार दिया गया।

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी द्वारा मनेर प्रखंड में वर्ष 2002 से वर्ष 2006 के बीच विभिन्न विकास योजनाओं में हुए जालसाजी, धोखाधड़ी और अपराधिक साजिश के तहत जाली कागजात तैयार कर फर्जी लोगों के बीच सरकारी राशि का बन्दरबॉट कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने, शिक्षा मित्र की नियुक्ति, बाढ़ राहत वितरण, इन्दिरा आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं में अनियमितता बरतने के संबंध में प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, जिसके आधार पर श्री इस्तियाज अहमद करीमी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-57/2009 दिनांक 22.05.2009 धारा 467/468/471(ए)/420/409/120(बी) भा0दि0व0 एवं 13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ0नि0अधि0, 1988 के अन्तर्गत अंकित किया गया।

(ख) अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव में श्री करीमी द्वारा अपने कार्यकाल में अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक ही परिवार के चार सदस्यों के नाम से इन्दिरा आवास आवंटित करने और अन्य अभियुक्तों एवं आवंटियों के साथ मिलकर बिना मकान बनाये सरकारी राशि की निकासी करने तथा राशि का भुगतान गाँव में नहीं रह रहे फर्जी लोगों को भुगतान किये जाने के स्पष्ट मौखिक एवं स्थलीय साक्ष्य को आधार बनाया गया था। निम्नलिखित योजनाओं में श्री करीमी के द्वारा राशि की निकासी दर्शायी गई थी :-

(i) योजना सं0-87/05-06,

(ii) योजना सं0-91/05-06 एवं

(iii) योजना सं0-26/05-06 में मकान नहीं बना, परन्तु रुपये की निकासी कर ली गई।

(iv) योजना सं0-90/05-06 में राशि का भुगतान लाभार्थी को नहीं किया गया परन्तु रुपये की निकासी की गई।

(v) योजना सं0-4/04-05 घर नहीं बना है।

(vi) योजना सं0-05/04-05 घर नहीं बना है।

इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कांड के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 22.09.2013 को अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव को पुलिस अधीक्षक को दिया गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो के पत्रांक 2069 दिनांक 03.01.2013 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था।

(ग) कांड के अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री इस्तियाज अहमद करीमी के द्वारा एक ही परिवार के चार लोगों को इंदिरा आवास आवंटित करने की बात सत्य नहीं है। श्री करीमी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर के पद पर रहते हुए इंदिरा आवास योजना में मात्र तीन लाभार्थी को ही इंदिरा आवास के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई थी और प्रथम किस्त के रूप में अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन मकान नहीं बनाने पर उनके द्वारा दूसरी किस्त विमुक्त नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2002 से वर्ष 2006 के बीच मनेर प्रखंड जिला पटना से संबंधित है, तथा श्री करीमी मनेर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर दिनांक 13.07.2004 से 06.02.2006 तक पदस्थापित थे। जिन लाभुकों को अग्रिम राशि दी गई वह निम्न प्रकार से हैं :-

- (ii) योजना सं०-04/04-05- देवन्ती देवी, पति विश्वनाथ राय, बी०पी०एल० सं० 8465 में इंदिरा आवास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मो० करीमी द्वारा दी गई थी और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी उनके द्वारा किया गया लेकिन लाभुक द्वारा मकान नहीं बनाने पर दूसरी किस्त उनके द्वारा विमुक्त नहीं की गई।
- (iii) योजना सं०-05/04-05- रामजप राय, पिता बाबु लाल राय बी०पी०एल० सं० 8457 में इंदिरा आवास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मो० करीमी द्वारा दी गई थी और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी उनके द्वारा किया गया लेकिन लाभुक द्वारा मकान नहीं बनाने पर दूसरी किस्त उनके द्वारा विमुक्त नहीं की गई।
- (iii) योजना सं०-02/04-05- सुदामो देवी, पति शारदा राम बी०पी०एल० सं० 9382 के लाभार्थी को प्रशासनिक स्वीकृति श्री इस्तियाज अहमद करीमी द्वारा दी गई थी और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी उनके द्वारा किया गया लेकिन लाभुक द्वारा मकान नहीं बनाने पर दूसरी किस्त उनके द्वारा विमुक्त नहीं की गई।
- अन्य योजनाओं यथा (क) योजना सं०-87/05-06 (ख) योजना सं० 91/05-06
- (ग) योजना सं०-26/05-06 तथा (घ) योजना सं०-90/05-06 में श्री करीमी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई थी। उक्त चारों योजना इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर के कार्यकाल के बाद स्वीकृत की गई है। श्री करीमी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी सरकारी निर्देश का अनुपालन करते हुए मात्र तीन योजनाओं में इन्दिरा आवास योजना हेतु प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई है तथा आवास निर्माण कार्य नहीं किये जाने के कारण दूसरी किस्त विमुक्त नहीं की गई।

अन्य योजनाओं में श्री करीमी की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई।

उक्त तथ्यों के आधार पर श्री करीमी को उनके विरुद्ध प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों के लिए दोषमुक्त किया गया।

7. श्री करीमी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण, पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि इंदिरा आवास योजना सं० 04/2004-05, 05/2004-05 एवं 02/2004-05 में श्री करीमी द्वारा प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया लेकिन लाभुक द्वारा मकान नहीं बनाये जाने के फलस्वरूप दूसरी किस्त उनके द्वारा विमुक्त नहीं की गयी। अन्य योजना यथा योजना सं०-87/05-06, योजना सं० 91/05-06, योजना सं०-26/05-06 एवं योजना सं०-90/05-06 में श्री करीमी द्वारा इन चारों योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति इनके कार्यकाल के बाद स्वीकृत की गई थी। श्री करीमी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी सरकारी निर्देश का अनुपालन करते हुए मात्र तीन योजनाओं में इन्दिरा आवास योजना हेतु प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई है तथा आवास निर्माण कार्य नहीं किये जाने के कारण दूसरी किस्त विमुक्त नहीं की गई। इसके अलावा शेष योजनाओं में इनकी कोई संलिप्तता नहीं पायी गयी। इस प्रकार श्री करीमी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

8. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री करीमी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रासंगिक थाना कांड में दोषमुक्त पाये जाने तथा जाँच प्रतिवेदन में आरोप अप्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के फलस्वरूप श्री करीमी के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17567 दिनांक 19.12.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

9. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री इस्तियाज अहमद करीमी (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 571/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर सम्प्रति निदेशक (उर्दू) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17567 दिनांक 19.12.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भे

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं० 2/आरोप-01-19/2016-सा०प्र०-6826

संकल्प

6 जून 2017

मो० नासिर हुसैन (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 720/11, वरीय उप समाहर्ता-सह- तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता, बक्सर सम्प्रति उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा, बक्सर में संचालित खाता रोकड़ बही, चेक बुक, चेक पंजी आदि का प्रभार सहायक नाजिर को नजारत शाखा, बक्सर के ज्ञापांक 08-0018/नजा० दिनांक 14.01.2015 देने के आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 08-0565 दिनांक 28.07.2016 द्वारा साक्ष्य सहित गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

2. मो0 हुसैन से उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 14539 दिनांक 26.10.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं मो0 हुसैन के पत्रांक 2790 दिनांक 08.11.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 16250 दिनांक 06.12.2016 एवं 533 दिनांक 17.01.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 10-0967 दिनांक 05.04.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी के स्पष्टीकरण पर असहमति व्यक्त की गयी।

3. प्रतिवेदित आरोपों पर मो0 हुसैन से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा समर्पित मंतव्य पर सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 हुसैन के विरुद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. जिला पदाधिकारी, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को देंगे।

5. मो0 नासिर हुसैन (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 720/11, वरीय उप समाहर्ता-सह-तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता, बक्सर सम्प्रति उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>